

संपादकीय

मणिपुर की चिंता

मणिपुर की राजधानी इंफाल में सोमवार को भड़की हिंसा और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगाने, इंटरनेट सेवाएं रद्द करने और सेना बुलाने की राज्य सरकार की विवशता समझी जा सकती है। निस्संदेह, यह दुखद स्थिति है, पर उपद्रवियों को काबू में करने का यह आखिरी रास्ता है, जिस पर कोई भी सरकार मजबूरी में ही कदम बढ़ाती है। पिछले कई हफ्तों से पूर्वोत्तर का यह सूबा अशांत है और वहां बड़ी संख्या में मैतेई व कुकी समुदाय के लोगों को हिंसा की वजह से अपने ही प्रदेश में दरबंदर होना पड़ा है। अनगिनत घरों, उपاسना स्थलों के राख होने और करीब 70 लोगों की मृत्यु के ब्योरे हालात की गंभीरता बताने के लिए काफी हैं। विडंबना यह है कि इस सूरते-हाल में जिन लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक वैमनस्य व सामुदायिक खटास को मिटाने की कोशिश करेंगे, वही आग में भी डालने की कार्रवाई कर रहे हैं। सोमवार को भड़की हिंसा के लिए एक पूर्व विधायक और उनके कुछ समर्थकों की गिरफ्तारी इसकी तस्दीक करती है। आरोप है कि पूर्व विधायक और उनके समर्थकों ने हथियार

के जोर पर समुदाय विशेष के लोगों को अपनी दुकानें बंद करने को बाध्य किया, जिसके कारण इंफाल में हिंसा नए सिरे से भड़क उठी। यही नहीं, राज्य के कई सत्तारूढ़ विधायकों के सियासी सुर भी उकसाने वाले सुनाई पड़े हैं, जबकि उन्हें इस वक्त ऐसे किसी भी बयान या कदम से खास परहेज बरतना चाहिए, जो राज्य और केंद्र सरकार की शांति-स्थान्‍यता की कोशिशों को पलीता लगाते हों। इस वक्त शांति मणिपुर की पहली आवश्यकता है। इसके दो बड़े जातीय समुदायों के दिलों में एक-दूजे के लिए जो कुटुना पैदा हुई है, उसे पाने की हरमुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। यह अफसोसनाक है कि जब केंद्र सरकार की राजनीतिक-आर्थिक सक्रियता से पूर्वोत्तर में स्थायी शांति की उम्मीदें जगने लगी थीं और लगने लगा था कि देश की मुख्यधारा से उसका जुड़ाव बढ़ रहा है, तब हिंसा के इस सिलसिले ने नई आशकाओं और शक-शुद्धे को जन्म दे दिया है। मणिपुर की स्थिति पर इसलिए भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का समूचा ताना-बाना एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है और इन राज्यों में कई जातीय समूहों के बीच हिंता के टकराव का एक लंबा इतिहास है। ऐसे में, यदि मणिपुर के हालात लंबे वक्त तक तनावपूर्ण बने रहे, तो इसकी आंच अन्य सूबों में पहुंच सकती है।

लगाते हों। इस वक्त शांति मणिपुर की पहली आवश्यकता है। इसके दो बड़े जातीय समुदायों के दिलों में एक-दूजे के लिए जो कुटुना पैदा हुई है, उसे पाने की हरमुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। यह अफसोसनाक है कि जब केंद्र सरकार की राजनीतिक-आर्थिक सक्रियता से पूर्वोत्तर में स्थायी शांति की उम्मीदें जगने लगी थीं और लगने लगा था कि देश की मुख्यधारा से उसका जुड़ाव बढ़ रहा है, तब हिंसा के इस सिलसिले ने नई आशकाओं और शक-शुद्धे को जन्म दे दिया है। मणिपुर की स्थिति पर इसलिए भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का समूचा ताना-बाना एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है और इन राज्यों में कई जातीय समूहों के बीच हिंता के टकराव का एक लंबा इतिहास है। ऐसे में, यदि मणिपुर के हालात लंबे वक्त तक तनावपूर्ण बने रहे, तो इसकी आंच अन्य सूबों में पहुंच सकती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को विश्वास बहाली के लिए स्थानीय नेताओं को भरपore में लेना चाहिए। हमने उपद्रवग्रस्त पंजाब, जम्मू-कश्मीर में यह देखा है कि ऊपर से थोपी गई रणनीति के बजाय स्थानीय कोशिशें ज्यादा प्रभावी साबित हुई थीं। पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार ने पिछले नौ वर्षों में जितनी योजनाएं शुरू की हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वहां शांति की दरकार है। फिर पूर्वोत्तर की सरकारों को यह नहीं भूचना चाहिए कि वे जिस ‘सशस्त्र बल विशेष शक्तियां कानून’ को हटाने के मनसूबे बांध रही हैं, यह तभी मुमकिन होगा, जब वहां स्थायी शांति की कोई सूरत नजर आएगी। वैसे भी सरहदी इलाका होने के कारण देश की सुरक्षा के लिहाज से इनमें से कई प्रांत संवेदशील हैं। इसलिए मणिपुर में जल्द शांति बहाल हो और लोगों की ज़िंदगी पट्टी पर लौटे, इसके लिए बीरेन सिंह सरकार को उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती के साथ-साथ पीढ़ीतों के जखम पर मरहम रखना होगा।

न्यायपालिका और सरकार में नहीं कोई मतभेद

केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिंजिजू को न्यायपालिका से जुबानी जंग की कीमत चुकानी पड़ी। न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम पर आक्रामक रख अख्तियार करने वाले रिंजिजू के चलते सरकार भी असजज थी। इससे पहले कोई भी राजनेता या मंत्री न्यायपालिका को लेकर इतना तल्लख नहीं रहा। किरण को फिलहाल पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है और उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। कानून मंत्री का पदभार संभालने के बाद मेघवाल का बयान कि न्यायपालिका और सरकार में कोई मतभेद नहीं है, बल्कि दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। संविधान में सवकी अपनी सीमाएं हैं और उसी के हिसाब में काम होता है। अशय साह है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच रिश्तों में कसेलापन था। रिंजिजू जिस तरह बिना लाग-लपेट के कॉलेजियम सिस्टम की बखिया उधेड़ते रहे, उससे एक बात तो साफ दूरियां दिखती थी। कभी कजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अंकल जज सिंड्रोम करार देना ही या कुछ जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा ऐसे बयानों को कानून मंत्री के तौर पर किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हां, ललितम मालों पर कार्य करने के तौर-तरीकों को बदलने की जगह बेवजह के विवादित बयानों का सहारा लिया जाएगा तो हालात और ज्यादा खराब ही होंगे। इस बात को लगता है सरकार ने समझा, तभी उन्हें इस पद से हटयाा भी गया। इस बदलाव में एक खास बात यह रही कि मेघवाल जिस राज्य राजस्थान से आते हैं वहां इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मतभिन्नता रही है। मेघवाल को अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर पार्टी राज्य में एक संदेश दिया है। चूंकि मेघवाल दलित समुदाय से आते हैं तो नि:संदेह राज्य में इस तबके के वोटरों को अपने पक्ष में करने में उन्हें आसानी होगी। बहरहाल, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के आखिरी साल में कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं। लिहाजा, ऐसे मंत्री की जरूरत होगी जो सबको साथ मिलाकर चल सके और सरकार के काम को सहजता से पूरा कर सके। मेघवाल इस मामले में सर्वोत्तम चयन हो सकते हैं क्योंकि उनका भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर लम्बा अनुभव रहा है। देखना है, इस फेरभदल के बाद न्यायपालिका के साथ सरकार के संबंध कैसे रहते हैं।

गारटियां ठीक हैं, लेकिन...

विकसित होने की महत्वाकांक्षा रखने वाली किसी व्यवस्था में आवश्यकता लोगों को सक्षम बनाने की होती है। भारत में भी आजादी के बाद हुआ यह सीमित प्रयोग सफल रहा था। लेकिन पिछले तीन-चार दशकों में उलटी गंगा बह पड़ी है। काग्रिस ने अपने चुनावी वायदे के मुताबिक सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में पांच गारटियां पर अमल की मंजूरी दे दी। यह निर्बिवाद है कि इन गारटियों से समाज एक बड़े तबके- खास कर महिलाओं को ऐसी सहायता मिलेगी, जिसकी इस समय बहुत जरूरत है। ऐसे उपायों को रेवडी कहकर उनका मजाक उड़ाना असल में आम जन के प्रति बैठे गहरे पूर्वाग्रहों और अपमान भाव की अभिव्यक्ति है। जिस समय हर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हर सेवा का व्यापारीकरण कर दिया गया है और पूरी अर्थनीति एकाधिकार जमा चुके पूंजीपतियों के हित में ढाल दी गई है, तात्कालिक राहत के तौर पर ऐसे उपायों की जरूरत बढ़ गई है। इसके बावजूद इन उपायों के जरिए राहत पहुंचाने की सोच पर बहस की आवश्यकता है। संसाधन का सवाल अप्रसांगिक नहीं है। यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि अगर जन-कल्याण के लिए कोई सरकार जितने संसाधन बचा या जुटा सकती है, अगर उन्हें फौरी राहत पर ही खर्च कर दिया जाए, तो समाज की जड़ों के निर्माण तथा दीर्घकालिक विसा की बुनियाद को मजबूत करने के कार्यक्रमों के लिए धन कहां से आएगा?

विचार

आखिर वह ‘असाधारण परिस्थिति’ थी क्या, जिसके लिए अभी कार्यपालिका को तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हुई। हमारी नजर स्वाभाविक तौर पर आठ दिन पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफजाती है। ताजा अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य अदालती फैसले के प्रभाव को कम करना जान पड़ता है। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले सेवाओं को नियंत्रित करने और दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण की शक्ति में उसे सर्वोच्चता हासिल थी।

वृंदा भंडारी, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

बीते शुक्रवार की देर शाम राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया, जिसने सेवाओं पर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लीं। उसके बजाय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उप-राज्यपाल (एलजी) को दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण व पोस्टिंग से जुड़े मसलों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया। नए अध्यादेश में नौकरशाहों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित मुद्दों पर फैसले लेने के लिए एक वैधानिक निकाय ‘राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण’ का गठन किया गया है, जिसमें तीन सदस्य होंगे- दिल्ली के मुख्यमंत्री, यहां के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव। इसका अर्थ यह है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के फैसले को दो वरिष्ठ नौकरशाह, जो निश्चय ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे, वीटो या खारिज कर सकते हैं।

यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 11 मई को सर्वसम्मति से पारित फैसले के मद्देनजर लाया गया है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने उप-राज्यपाल के बजाय लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई स्थानीय सरकार को दिल्ली की सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार दिया था। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने माना था कि भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर जनता द्वारा निर्वाचित दिल्ली सरकार के पास ही नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के मुद्दे पर अंतिम विधायी और समान विस्तार वाली

कार्यकारी शक्ति होनी चाहिए। अदालत के फैसले के पीछे तर्क यह था कि चूंकि सिविल सेवक ‘सरकारी नीतियों’ के क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं’, इसलिए निर्वाचित सरकार इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वह अपनी सेवाओं में तैनात नौकरशाहों को नियंत्रित कर सके और उनकी जिम्मेदारी तय कर सके।

जाहिर है, ताजा अध्यादेश से प्रक्रियात्मक, औचित्य और बुनियादी मुद्दों से जुड़े तमाम तरह के सवाल पैदा हो गए हैं। सामान्यतः अध्यादेशों को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत तब जारी किया जाता है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, और जब राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जिसके लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 123 बनाने के पीछे ‘अति-आवश्यकता’ की भावना रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसका उल्लेख यहां उचित होगा। उस फैसले में कहा गया था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को इसलिए दी गई है, ताकि जब ‘अप्रत्याशित हालात बन जाएं और उनसे निपटने के लिए विधायी उपायों की दरकार हो’, तब कोई सांविधानिक शून्य की स्थिति न बनने पाए। सात न्यायाधीशों



की पीठ ने कहा था कि अध्यादेश जारी करना एक असाधारण शक्ति है, जिसका मकसद सांविधानिक जरूरतों को पूरा करना है।

आखिर वह ‘असाधारण परिस्थिति’ थी क्या, जिसके लिए अभी कार्यपालिका को तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हुई। हमारी नजर स्वाभाविक तौर पर आठ दिन पहले दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ जाती है। ताजा अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य अदालती फैसले के प्रभाव को कम करना जान पड़ता है। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले सेवाओं को नियंत्रित करने और दिल्ली में नौकरशाहों के स्थानांतरण की शक्ति में उसे सर्वोच्चता हासिल थी। जाहिर है, सर्वसम्मत फैसले में हारने के तुरंत बाद

क्या वैज्ञानिकों ने नहीं बताया आइसक्रीम के फायदे

मनु जोसेफ, पत्रकार और उपन्यासकार

अप्रैल में एक कथा सामने आई कि कई सालों से वैज्ञानिकों ने एक आश्चर्यजनक खोज को दबा रखा है। खोज यह है कि आइसक्रीम स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है। द अटलांटिक पत्रिका ने जन-स्वास्थ्य इतिहासकार डेविड मेरिट जॉन्स द्वारा द आइसक्रीम कांसपिरेसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह कहानी 2018 में शुरू होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक डॉक्टरेट छात्र के शोध ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि मधुमेह रोगियों में एक दिन में आधा कप आइसक्रीम खाने से दिल की समस्याओं का जोखिम कम होता है। यह खोज बहुत दिलचस्प लगी, तो वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने उन्हें फिर से जांच के लिए कहा। तब भी आइसक्रीम के फ्रयदे सभी कठोर हमलों से बचे रहे।

यह पहली बार नहीं है, जब हार्वर्ड में एक वैज्ञानिक अध्ययन ने आइसक्रीम को स्वास्थ्य लाभ से जोड़ा है, 20 साल पहले, शोधकर्ता मार्क ए पेरो ने 5,000 से अधिक वयस्कों के हृदय पर भोजन के असर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया था। कम वसा वाले डेयरी उत्पाद की



बात करें, तो स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। तब कम वसा वाले डेयरी उत्पाद में मुख्य रूप से आइसक्रीम शामिल थी, जिसका लाभकारी प्रभाव दिखा था। आइसक्रीम से अधिक वजन वाले लोगों के प्री-डायबिटिक होने की आशंका को कम होते पाया गया था।

द अटलांटिक में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद, ‘क्या आइसक्रीम स्वास्थ्यकर हो सकती है?’ शीर्षक से रिपोर्टों की बाढ़ आ

गई। पत्रकारिता में अगर आप किसी शीर्षक में प्रश्नवाचक चिह्न देखते हैं, तो इसका नतीजा निकालते हैं कि लेखक को उत्तर पता नहीं है। बाद में प्रकाशित रिपोर्टों में एक अनकही उम्मीद का उत्साह था कि आइसक्रीम न केवल ठीक खाद्य पदार्थ है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी है, अगर इसको रोज कम मात्रा में खाया जाए। हालांकि, तब वैज्ञानिक समुदाय इसे सच मानने को तैयार नहीं था। वास्तव में, द

उस नाते हिसाब लगाए कि मोदी सरकार में नोटबंदी के बाद से व्यापारियों पर कितनी तरह के जुल्म हुए हैं? वे कितनी तरह की परेशानियों से गुजरो हैं? ठिक यही लड़के-लड़कियों को है। आंदोलन नहीं कर सकता कि हाल की गेंहु फसल में मौसम गड़बडी से किसानों को कैसा जबरदस्त नुकसान हुआ है? न ही गांवों में पहले की तरह मनरेगा में काम मिल रहा है। व्यापारी-किसान के बाद शहर-कस्बों के मध्यवर्ग पर सोचे तो महंगाई, बेरोजगारी की बेहाली और बेरोजगार लड़के-लड़कियों की मानसिक दशा अकल्पनीय।

मैं इस सबके लिए अकेले मोदी सरकार व भाजपा-संघ को ही दोषी नहीं मानता हूं। मोदी सरकार के साथ विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने भी तो जीएसटी के उस ताने-बाने को मंजूरी दी थी जो अफसरों ने इंस्पेक्टर राज के अनुकूल

कानून-नियमों से बनवाया। हालांकि तथ्य यह भी है कि नरेंद्र मोदी ने इंस्पेक्टर राज खत्म करने और सबकुछ डिजिटल व पारदर्शी होने की घोषणाएं की थी। सिस्टम

उसने यह अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमतर करने का प्रयास किया है। अध्यादेश में कहा गया है कि यह इसलिए जारी किया गया है, क्योंकि यह ‘व्यापक राष्ट्रीय हित में है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई केंद्र सरकार के जरिये पूरे देश के लोगों की कुछ भूमिका राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में हो’, और ‘अपनी राजधानी पर शासन करने की राष्ट्र की इस लोकतांत्रिका इच्छा’ को प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया जाता है। इस तरह से केंद्र ने (उप-राज्यपाल के माध्यम से) सेवाओं पर दिल्ली सरकार का अधिकार अपने हाथों में ले लिया।

यह जगजाहिर तथ्य है कि नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का अधिकार सीधे तौर पर शासन की दक्षता व प्रभावशीलता से जुड़ा होता है, क्योंकि ये (गैर-निर्वाचित) नौकरशाह ही होते हैं, जो नीतियों को जमीन पर लागू करने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए, अध्यादेश की भाषा ऐसी जान पड़ती है कि केंद्र सब कुछ अपने हाथों में रखने के प्रयास कर रहा है, और लोकतांत्रिक जवाबदेही, प्रतिनिधि सरकार व सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को कमतर करना चाहता है।

इस अध्यादेश को जारी करने का समय भी काफी खास है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपना फैसला सुनाया था और 19 मई

अटलांटिक की रिपोर्ट का मुख्य संदेश यह नहीं था कि आइसक्रीम फायदेमंद हो सकती है, बल्कि यह था कि आइसक्रीम पोषण वैज्ञानिकों की नजर में अलोकप्रिय थी। यदि कोई अन्य खाद्य पदार्थ होता, जिसमें चीनी की मात्रा नहीं होती, तो उसे लोकप्रिय ढंग से स्वीकार कर लिया जाता, पर आइसक्रीम को स्वीकार नहीं किया गया। पोषण विशेषज्ञों और मीडिया ने भी एक जिम्मेदारी की भावना के तहत इस तथ्य को दबा दिया।

जॉन्स ने 2014 में एक अध्ययन का उल्लेख किया था कि दही का अधिक सेवन टाइप-2 मधुमेह के जोखिम को कम करता है, जबकि डेयरी के अन्य उत्पाद ऐसा नहीं करते। दही को खाद्य पदार्थों में महानायक माना जाता है और उसके लिए होने वाली अच्छी-अच्छी बातों पर कोई सवाल नहीं खड़े करता है। यह सच नहीं था कि अध्ययन में कोई अन्य ऐसा डेयरी उत्पाद नहीं मिला, जो मधुमेह के जोखिम को कम करता हो। जांच में पाया गया कि यही काम आइसक्रीम ने भी किया। वास्तव में, आइसक्रीम का अच्छा प्रभाव दही की तुलना में अधिक अनुकूल था। फिर भी, ज्यादातर वैज्ञानिकों ने यही सोचा कि वे कैसे आइसक्रीम के

की देर शाम अध्यादेश जारी कर दिया गया, जबकि उसी दिन शीर्ष अदालत छुट्टियों के लिए बंद हो रही थी। इसके साथ ही कुछ अन्य मसले भी इसके साथ नत्थी हैं। मसलन, अदालती फैसले के आधार को हटाकर, जो कि विधायी अधिनियम द्वारा किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बेअसर करने की कसौटी पर क्या यह अध्यादेश खरा उतरता है, या सीधे-सीधे यह अदालत का विरोध है, जो अस्वीकार्य माना जाता है? अदालत को इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या यह अध्यादेश दिल्ली के शासकीय ढांचे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 239 (अ)(अ) में संशोधन किए बिना उसके फैसले को निष्प्रभावी बनाता है? सुप्रीम कोर्ट को संघवाद पर इस अध्यादेश के प्रभाव के बारे में भी गौर करना होगा, जो संविधान का एक बुनियादी हिस्सा है।

निस्संदेह, इस बात की पूरी संभावना है कि इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी जाएगी। जब भी ऐसा किया जाएगा, यह लाजिमी है कि शीर्ष अदालत मामले को सुनवाई तत्काल आधार पर करे और शीघ्रता से इस मसले को निपटारा करे। देरी के कारण होने वाली न्यायिक सुस्ती कहीं इतनी लंबी न खिंच जाए कि यथास्थिति ही बनी रह जाए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

लाभ का खंडन कर सकते हैं। आखिर सच क्या है? जॉन्स इशाार करते हैं, ब्राउन राज्स की तुलना में भी आइसक्रीम ज्यादा लाभकारी है। इसमें विटामिन और प्रोटीन भी होता है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है, पर तब क्या हो, अगर लोगों को आइसक्रीम को मुख्य भोजन बनाने के लिए प्रेरित किया जाए? एक यू-ट्यूबर ने यही किया और उसका वजन घट गया, पर उसे आइसक्रीम से नफरत भी होने लगी।

फिलहाल, मैं उन वैज्ञानिकों के पक्ष में हूं, जो यह स्वीकार करने से पहले पूरी तरह आक्षेप्त होना चाहते हैं कि आइसक्रीम हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्द्धक है। हो सकता है कि जो लोग आइसक्रीम नहीं खाते, वे कुछ अन्य खराब चीजें खाते हैं। यह भी एक तथ्य ही है कि खाने के लिए आधुनिक दुनिया ने बेकार की चीजें भी बहुत बनाई हैं। आइसक्रीम संबंधी साजिश का सबसे दिलचस्प रहस्योद्घाटन यह है कि विज्ञान में भी ऐसे चौकीदार हैं, जो यह तय करते हैं कि किसे सिद्ध तथ्य के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और किसे गलत संकेत के रूप में बदनाम किया जाना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सता जनविरोधी और बुद्धीनाशी

कारोबारियों (अदानी-अंबानी जैसों के छोड़े) का धंधा वैसे ही अधमरा था। अब लगता है सरकार ने इंडी, सीबीआई,

नरवर्षसिंहराव सरकार से पहले नकदी से दो नंबर में विदेशी करेंसी खरीद कर, हवाला लेन-देन से विदेश में भुगतान हुआ करता था। वह काली व्यवस्था वापिस लौटती लगती है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बैंक खातों से जुड़े क्रेडिट कार्ड से विदेश में यदि कोई भारतीय बड़ा भुगतान करेगा तो उस पेमेंट पर सरकार बीस प्रतिशत टैक्स आटोमेटिक जमा कर लेगी। फिर इनकम टैक्स रिटर्न आदि की प्रक्रिया। सोचे, क्या इससे मध्य-उच्च वर्गीय प्रोफेशनल या कारोबारी या मंहंगी विदेश ख़ाता करने वालों के दिल-दिमाग में टैक्स आंतकवाद का खौफ नहीं बनेगा। सोचे, कांडीहोल्डर का अपने खाते से पेमेंट ळव ख़ाता जिसमें टैक्स दे कर उसकी सच्ची बचत, सच्ची इनकम जमा है और उसे वह विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करता तो उसके वापिस जबरदस्ती टैक्स वसूलने की चालबाजी क्या व्यवस्था का नागरिक से धोखा व छल नहीं है? इस छल के लिए नरेंद्र मोदी व निर्मला सीतारमण का दिमाग जिम्मेवार या जनता को टैक्स टेरर से लूटने वाली अफसशही का आईडिया? एक और उदाहरण। जिस दिन कोलकत्ता-पुरी की वंदे मातरम ट्रेन चालू हुई उसी दिन खबर देखने को मिली कि कोविड काल में रेल मंत्रालय ने आम यात्री

भाड़े की रेट को10 रु प्रति किलोमीटर से बढ़ा कर30 रुपए किया था उसे वापिस दस रु करने के लिए ममता बनर्जी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। ईस्टर्न रेलवे पैसेंजर एक्सप्रेसिशन की मांग के हवाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्री से अपील की कि रेलवे के हावडा डिविजन ने कोविड के बहाने जो रेट बढ़ाई थीउसे कम किया जाए। इलाके में लोग गरीब। वे रोजीरोटी के लिए लोकल ट्रेन से रोजाना सफर करते हैं।

सोचे, ऐसा कैसे जो लोकल ट्रेन के बेहद गरीब यात्रियों से भी कोविड काल में बढ़ाया गया भाड़ा लगातार वसूला जाता हुआ। एक तरफ हाईफाई वंदे मातरम ट्रेन का महा महंगा टिकट तो दूसरी ओर डेली मजदूर पैसेंजरों से भी भारी वसूली। ऐसा पूरे भारत में आवाजही के हर साधन पर लागू है। छोटे हवाई सर्किट के टिकट तीस-तीस हजार में बिक रहे हैं तो एक्सप्रेस वे, हाईवे पर कार का एकतरफा सफर 800-1000-1200 रु का टोल बिल बनवाता है।

सो पहली बात, आम आदमी-व्यापरी- किसान को ध्यान में रखकर काम नहीं, दिखावा और रेवडियां हैं। दूसरी बात साफ का पूरा तंत्र, उसकी अफसरशाही वापिस चोर दरवाजे सरकार को रेवेन्यू के नाम पर समाजवादी दिनों का आंतक-खौफ बनवा दे रही है। छोटे-छोटे जिलों-कस्बों में इंस्पेक्टर राज घर-घर पहुंचता हुआ है।

Sargam

Musicals

Deals in All Kinds of Musical Instrument Sales & Repair

DURG:-
Near Tarun Adlabs
Station Road, Durg (C.G.)
Durg. Ph. 2330588, 9826660688

RAIPUR:-
Near Manju Mamta
Reaustaurant, M.G. Road
Raipur. Ph. 4013288, 9303876196

स्टेशन रोड, इंदिरा मार्केट,

दुर्ग के प्रतिष्ठित संस्थान

विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-

9827806026,

7869620239

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में

COMPLETE FAMILY SALON

हेयर रिस्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

पहले

बाद में

JITU'Z

CUT N SHINE

93009-11331

रंगोली बेगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

ADMISSION OPEN

12th CLASS

REGULAR STUDENT

GET CLASS 11th SYLLABUS CLASSES for FREE

APPLY NOW

COMMERCE GURU

www.commerceguru.in

+91 9644454810

+91 8103338634

श्रीकंचनपथ

छत्तीसगढ़

इनकम TAX ITR फाईल

बनवायें मात्र 500/- में

TDS, GST, TAX Expert सम्पर्क- शेखर गुप्ता

9300755544

onlytds@gmail.com WWW.ONLYTDS.COM

बुधवार, 24 मई 2023

पेज-3

खास खबर

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने बच्चों को स्वर्ण प्राशन

रायपुर। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्प नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। चिकित्सालय के कौमारभृत्य बाल रोग विभाग में सवेरे नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक इसका सेवन कराया जाता है। यह औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, ध्वसन संबंधी एवं अन्य रोगों से रक्षा करने के साथ ही एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्प नक्षत्र तिथि में बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की आगामी पुष्प नक्षत्र तिथियों 24 मई, 20 जून, 18 जुलाई, 14 अगस्त, 10 सितम्बर, 7 अक्टूबर, 4 नवम्बर, 1 दिसम्बर और 29 दिसम्बर को बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा।

समर कैम्प का हुआ समापन

राजनांदगांव। जिले भर में शासकीय स्कूलों में समर कैम्प में खुशी एवं उत्साह का माहौल रहा। 8 मई से 22 मई तक आयोजित समर कैम्प का समापन हुआ। समर कैम्प में लगभग 15 हजार 400 बच्चे विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए। कलेक्टर डोमन सिंह की अनूठी पहल पर जिले भर में बच्चों के साथ ही अभिभावकों, शिक्षक एवं जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी-कर्मचारी सभी स्वच्छ से जुड़े रहे। कलेक्टर सिंह की सोच के अनुरूप बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए आयोजित समर कैम्प में बच्चों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने चित्रकारी सीखी तो किसी ने पेंटिंग व क्ले आर्ट। किसी ने गीत-संगीत, नृत्य, मेहंदी सीखी। गणित की गतिविधियों के साथ ही विविध खेल गतिविधियों में शामिल हुए। इसी कड़ी में कलेक्टर सिंह आज रेंगाकठरा में आयोजित समर कैम्प में शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर को बच्चों ने गीत गाकर सुनाया। उन्होंने कहा कि समर कैम्प बच्चों के माध्यम से बच्चों में निहित प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इससे उनमें झिझक की भावना दूर हो रही है और वे अपने मनपसंद गतिविधियों को सीख रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने स्नेहपूर्वक बच्ची झरना साहू से हाथ में मेहंदी लगावाई और बच्चों से समर कैम्प में संचालित गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीण परिवेश के अनुरूप बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार ने लिटिया, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने नंदई, एस्डीएम राजनांदगांव अरूण वर्मा ने भेंडीकला,सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव गुप्तेश्वरी रावटे ने इंदामरा के पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं में आयोजित समर कैम्प का निरीक्षण किया।

हमारी योजनाओं से आया परिवर्तन

अब वनांचल के लोग वनकर्मियों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानते हैं : भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वाली लोगों की चिंता भी जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि भू-जल स्तर पर्याप्त होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1 करोड़ 19 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया है।



मिला नरवा योजना अच्छी है। हर जगह आदिवासियों ने नरवा योजना को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव के लोग और वनसंरक्षकों की दोस्ती हो गई है।

आदिवासी और वनांचल में रहने वाले लोग वन विभाग को अपना दुश्मन नहीं मानते। वन विभाग के अधिकारी जंगल जाते हैं तो लगता है, हमारे लिए कोई नई योजना आयी है, छत्तीसगढ़ में यह परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाए जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। इसके साथ ही इनकी बिक्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वन विभाग सिर्फ जंगल का अभिभावक नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों का भी अभिभावक है।

ऐसे आपसी संबंध विकसित करने में हम सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने से आमदनी बढ़ेगी, हरियाली रहेगी और जंगल भी बचे रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन के महत्व का पता चला। छत्तीसगढ़ से देश के कई इलाकों में ऑक्सीजन पहुंचायी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार के लघु वनोपज

की खरीदी हो रही है। जिससे लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ अर्जित हो रहा है।

भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक श्री चन्द्रप्रकाश गोयल ने मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि एवं जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं सर्वोपयोगी बनाने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल सिंह सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं चंद्र प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय कैम्पा के सीईओ सुभाष सिंह, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, पीसीसीएफ वी. श्रीनिवास राव, सहित देश भर से आए वानिकी विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बहराराई बिलासपुर में संचालित प्रथम आवासीय अकादमी को मिली बड़ी उपलब्धि

आवासीय हॉकी अकादमी बिलासपुर की खिलाड़ी गीता यादव का 'खेलो इण्डिया वार्षिक स्कॉलरशिप' में चयन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बी. आर. यादव. राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहराराई बिलासपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी से हॉकी खिलाड़ी कुमारी गीता यादव का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण की 'खेलो इण्डिया वार्षिक स्कॉलरशिप' के लिए किया गया है।



कुमारी गीता यादव को स्कॉलरशिप के तहत प्रतिवर्ष 6 लाख 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गीता यादव को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि

उनकी यह उपलब्धि बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। खेल एवं युवा कल्याण

मंत्री श्री उमेश पटेल ने गीता को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न खेल अकादमियों का निर्माण कर रही है। ताकी यहां से खिलाड़ी प्रशिक्षण पाकर देश का नाम रोशन करें।

खेलो इण्डिया नई दिल्ली द्वारा 16 से 20 मई 2023 तक एसेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया था। राजनांदगांव में आयोजित वेस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से नेशनल टीम की सदस्य रही कुमारी गीता यादव ने शानदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के आधार पर हॉकी की प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ी कु. गीता यादव का चयन खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के

लिए किया गया। बहराराई बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी एवं एथलेटिक्स की आवासीय अकादमी संचालित हैं। यहां पर आधुनिक प्रशिक्षण एवं बेहतर सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एक्सीलेंस सेंटर की मान्यता दी गई है। इस अकादमी में 95 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं। जिसमें हॉकी में 57, तीरंदाजी में 12 एवं एथलेटिक्स में 26 खिलाड़ी शामिल हैं। कुमारी गीता यादव की इस उपलब्धि पर खेल सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का, खेल संचालक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, बिलासपुर अकादमी के हेड कोच श्री विकास पॉल, हेड परफॉर्मंस मैनेजर सहित सभी अधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

बादल अकादमी में चलाया गया स्वच्छता अभियान

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। आसना स्थित बादल अकादमी में सोमवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कलेक्टर श्री विजय दयाराम के की अगुवाई में विभिन्न जनजातीय समुदायों के समाज प्रमुखों व सदस्यों के द्वारा बादल अकादमी के परिसर में स्वच्छता अभियान किया गया।

परिसर के स्वच्छता अभियान को लेकर समाज प्रमुखों और सदस्यों के साथ ही अकादमी के कर्मचारी सुबह से ही उत्साह के साथ जुटे और परिसर में उगे झाड़ियों और खरपतवारों की सफाई की। यहां सफाई के बाद इकट्ठा किए गए

झाड़ियों और खरपतवारों से खाद तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इस परिसर में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने की मंशा भी सभी ने जताई। उल्लेखनीय है कि शनिवार को कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा विभिन्न समाजों के प्रमुख और सदस्यों के साथ यहां संचालित गतिविधियों को तेज करने के संबंध में चर्चा की गई थी और उन्होंने इस अकादमी को यहां के जनजातीय समाजों की धरोहर बताते हुए यहां की गतिविधियों को तेज करने का आग्रह किया गया था। कलेक्टर ने परिसर में लगाए आम और अनार के पौधे परिसर की साफ सफाई के बाद यहां कलेक्टर श्री विजय द्वारा आम और अनार के पौधे भी लगाए गए।

श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र के लोगों को विभागीय योजनाओं से करें लाभान्वित - कलेक्टर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। शासन द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए विभिन्न लाभकारी योजना संचालित हो रही है, जिसका लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान करना सुनिश्चित करें। श्रम विभाग में इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित है, जिससे श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति के माध्यम से अतिरिक्त राशि मिलने से शिक्षा के माध्यम से उनका जीवन संवर सकता है।



सियान सहायता योजना, मेधावी छात्र-छात्रा योजना, मुख्यमंत्री नोनी शक्तिकरण सहायता योजना तथा विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अलंयेष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना जैसे विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि श्रमिकों, गर्भवती महिलाएं बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका आमजन को अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सभी रीपा गोठानों में काम करने वाले श्रमिकों का पंजीयन करने शिविर लगाने के निर्देश दिया। कलेक्टर श्री सिन्हा ने विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद सीईओ के माध्यम से समन्वय कर ब्लॉकवार

शिविर लगाए, श्रमिकों का पंजीयन, लाभ एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने निमग्न सफाई कामगार योजना अंतर्गत सफाई कामगारों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग, श्रम एवं नरगा जैसे योजनाओं से लाभ प्रदान करें। उन्होंने विभागीय अधिकारी को जनचौपाल के लॉबि आवेदनों का अतिशोघ्र निराकरण के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिन्हा ने इस दौरान जिला व्यापार उद्योग के कार्यों की समीक्षा की। महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग

केन्द्र श्री शिव कुमार राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु विभाग द्वारा 27 प्रकरण बना के भेजा गया, जिसमें बैंक के माध्यम से 12 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। इसी प्रकार उद्योगों की स्थापना के तहत जिले में सुक्ष्म, लघु, वृहद मिला कर कुल 12 उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे 217 लोगों को रोजगार मिला है। इसी प्रकार कलेक्टर श्री सिन्हा ने खादी, औद्योगिक सुरक्षा, रेशम हस्त शिल्प की समीक्षा करते हुए जानकारी ली। हस्त शिल्प के विभागीय अधिकारी ने बताया कि तरछा में बेल मेटल, कोसमनारा में बांस तथा सुपा में ट्रेनिंग प्रस्तावित है। इसके विक्रय हेतु प्रदर्शनी एवं सी-मार्ट में भेजा जाएगा। रेशम विभाग द्वारा बताया गया कि वृक्षा रोपण में अर्जुन के पौधे रोपे जायेंगे। कलेक्टर श्री सिन्हा ने खादी ग्रामोद्योग को संबलपुरी गोठान का निरीक्षण कर विभागीय योजना के लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर श्री सिन्हा ने योजना एवं सांख्यिकी विभाग को विधायक, सांसद से प्रस्ताव लेकर राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

जन-चौपाल कार्यक्रम में 68 आवेदन हुए प्राप्त

राजनांदगांव। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकगणों ने जन-चौपाल में अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित जन-चौपाल कार्यक्रम में अधिकारियों ने नागरिकगणों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनने के साथ ही शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है। जन-चौपाल कार्यक्रम में आज 68 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आवेदनों को ऑनलाइन पंजीयन करने के साथ ही संबंधित विभाग में भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जन-चौपाल कार्यक्रम में आज ग्राम रेंगाडबरी के इंदल सिंह ने अपनी बीज भूमि का वन अधिकार पट्टा प्रदाय करने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है।

ॐ साई राम

माँ पुस्तक भंडार

होलसेल में कापी-किताब एवं स्टेशनरी सामान मिलने का एक मात्र स्थान

पुरानी एवं नई पुस्तकें खरीदी व बेची जाती है

रावणभाटा, सुपेला, भिलाई (छ.ग.)

मो. 7489051024, 7770845578

BIG BRAND

Premium Store

30% Off

70001 78467

70008 73376

Near KPS school ,

Nehru Nagar ,Bhilai

Since 1972

CROWN® - TV

Choice Of Millions

LED Available 16 -20 -22 - 24 - 32-40-50-55-65

Premier sales

8959493000

Arhum Electronics

9926100315

A Leela Electronics

9425507772

Reena Electronics

9329132299

Shree Electronics

7000827361

Maa Durga Electronics

9827183839

Rohit Electronics

94242-02866

Authorised Distributors

For Chhattisgarh

Trade Enquiry: 98262-52372

खास खबर...

खाद्य मंत्री भगत की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक 26 मई को

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की प्रथम बैठक 26 मई को दोपहर 12 बजे मंत्रालय, महानदी भवन स्थित समिति कक्ष एस-2-12 में आयोजित की गई है। बैठक में संबंधित विभागीय सचिव, प्रबंध संचालक राज्य विद्युत कम्पनी, सदस्य छत्तीसगढ़ भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण, प्रबंधक लीड बैंक, दूरसंचार विभाग के निदेशक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिष्ठान आयोग के रजिस्ट्रार सहित अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

राशनकार्डधारी सदस्य आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक दे सकते हैं आधार नंबर

रायपुर। प्रदेश में पंजीकृत राशनकार्डधारी सभी सदस्यों का आधार नंबर प्रस्तुत करने की समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों को आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा 30 जून 2023 तक की गई है। अतः जिले में प्रचलित पंजीकृत सभी सदस्यों का आधार नंबर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर समय-सीमा में आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

हॉकी अकादमी की खिलाड़ी गीता को 'खेलो इंडिया वार्षिक छत्रवृत्ति' में चयन

रायपुर (ए)। बीआर यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई बिलासपुर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी से हॉकी खिलाड़ी कुमारी गीता यादव का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण की 'खेलो इण्डिया वार्षिक स्कॉलरशिप' के लिए किया गया है। कुमारी गीता यादव को स्कॉलरशिप के तहत प्रतिवर्ष 6 लाख 20 हजार रुपये दिए जायेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गीता यादव को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा की उनकी यह उपलब्धि बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने गीता को बधाई दी और कहा की राज्य सरकार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न खेल अकादमियों का निर्माण कर रही है। ताकी यहां से खिलाड़ी प्रशिक्षण पाकर देश का नाम रोशन करें।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देखा ईएमआर सिस्टम

बिना चीरे के न्यूरो सर्जरी के बारे में भी ली जानकारी, छत्तीसगढ़ में भी इसे अपनाने स्वास्थ्य विभाग साझेदारी की संभावना तलाशेगा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अध्ययन भ्रमण पर ऑस्ट्रेलिया गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अधिकारियों के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। टीम ने विगत 20 मई को क्रीसलैंड के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का भ्रमण किया था। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के साथ अध्ययन दौरे पर ऑस्ट्रेलिया गई टीम में स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदिपान और राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन शामिल हैं।

टीम ने गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल



में अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर वहां विकसित और लागू की गई ईएमआर (इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड) प्रणाली के बारे में जाना। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने

टीम के सामने इसका प्रस्तुतिकरण दिया। वहां के विशेषज्ञों ने अस्पताल की मजबूत आईटी सिस्टम का भी प्रेजेंटेशन दिया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्चायरोथॉन भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

इन्चायरोथॉन 1 जून को, भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता 4 जून को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं सर्वप्रथम 01 जून 2023 को कलिंगा विश्वविद्यालय परिसर में सॉल्यूशन फॉर वेस्ट यूटिलाइजेशन विषय पर इन्चायरोथॉन का आयोजन तीन वर्ग समूह में किया गया है। कलिंगा विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रथम वर्ग में कक्षा 10 वीं से 12 वीं, द्वितीय वर्ग में सभी स्नातक एवं तृतीय वर्ग में स्नातकोत्तर के छात्र एवं

छात्राएं भाग ले सकेंगे। प्रथम पुरस्कार 21 हजार रूपए, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रूपए एवं तृतीय पुरस्कार 11 हजार रूपए रखे गये हैं। प्रतियोगिता का द्वितीय चरण 05 जून को नवीन विश्राम गुह, सिविल लाईन, रायपुर में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 4 जून 2023 को प्रातः 10 बजे से न्यू कन्वेन्शन हॉल नवीन विश्राम गुह, सिविल लाईन, रायपुर में भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इन प्रतियोगिताओं का विषय है

’व्यक्तिगत आदतों एवं व्यवहारों में परिवर्तन लाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी करना” भाषण प्रतियोगिता दो आयु वर्गों 13 से 17 वर्ष व 18 से 21 वर्ष एवं पोस्टर प्रतियोगिता तीन आयु वर्ग 12 वर्ष तक, व 13 से 17 वर्ष व 18 से 21 वर्ष वर्ग में होगी, जिसमें पृथक-पृथक पुरस्कार दिये जायेंगे।

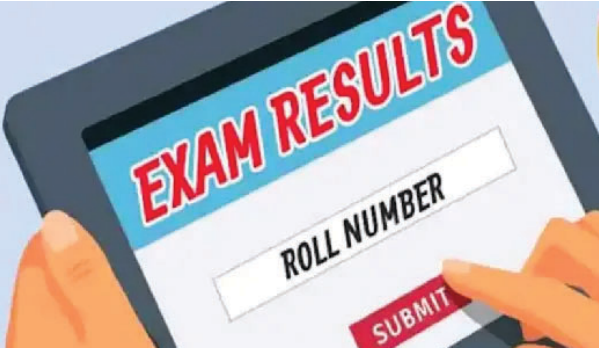
प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अपना पहचान पत्र एवं आयु प्रमाण-पत्र की छायाप्रतियाँ साथ लानी होंगी। रजिस्ट्रेशन प्रतियोगिता स्थल पर किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन हेतु प्रतिभागियों को प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप आकर्षक था। इस 34 हजार 161 परीक्षार्थी 05 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यू-सर्किट हाऊस, सिविल लाईस, रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित

हायर सेकेण्डरी परीक्षा का परिणाम 65.46 प्रतिशत तथा हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम 54.09 प्रतिशत रहा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए। हाई स्कूल का परीक्षाफल प्रतिशत 54.09 तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा का परीक्षाफल प्रतिशत 65.46 रहा। हाई स्कूल परीक्षा में कुल 37 हजार 471 छात्रों का पंजीयन हुआ था। इस 34 हजार 161 परीक्षार्थी 05 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यू-सर्किट हाऊस, सिविल लाईस, रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जायेगा।



तृतीय श्रेणी 6 हजार 923 विद्यार्थी से उत्तीर्ण हुए। कुल 18 हजार 465 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 65 हजार 557 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ था। इसमें 62 हजार 51 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 57 हजार 105 परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इनमें 9 हजार 653 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 15 हजार 180 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी से तथा 11 हजार 801 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कुल 37 हजार 383 विद्यार्थी

उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 4 हजार 883 विद्यार्थी आरटीडी योजनांतर्गत अवसर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 63 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोका गया है। उक्त परीक्षा परिणाम छात्र वेबसाइट <https://www.sos.cg.nic.in/> एवं <http://www.result.cg.nic.in> में प्राप्त कर सकते हैं एवं अनुत्तीर्ण छात्र आगामी परीक्षा के आवेदन फार्म अपने अध्ययन केन्द्र में जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

पंजीकृत 4850 मानस मंडलियों को मिली 2.43 करोड रूपए की प्रोत्साहन राशि

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत चयनित 4850 रामायण मानस मंडलियों को दो करोड़ 42 लाख 50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर विगत दो वर्षों से राज्य स्तरीय रामायण मंडली मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विजयी दल के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। सरकार की इस पहल से हमारी प्राचीन संस्कृति को पुनः स्थापित करने में सफलता हासिल की है। रामायण मंडली के



बीच मानस प्रतियोगिता में प्रदेश के रामायण मंडलियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विजेता दल को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला।

संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गरियाबंद जिले के चयनित 243 मानस मंडलियों को 12 लाख 16 हजार रूपए, बलौदाबाजार-भाटापारा के 92

मानस मंडली, को 4 लाख 60 हजार रूपए, बेमेतरा के 185 मानस मंडली को 9 लाख 30 हजार रूपए, दुर्ग के 12 मानस मंडली को 10 लाख 60 हजार रूपए, रायपुर के 189 मानस मंडली को 9 लाख 50 हजार रूपए, सक्ति के 514 मानस मंडली को 25 लाख 70 हजार रूपए, नारायणपुर के 31 मानस मंडली को 15 लाख 50 हजार रूपए, मुंगेली के 72 मानस मंडली को 3 लाख 60 हजार रूपए, मोहला-मानपुर-चौकी के 59 मानस मंडली को 23 लाख 95 हजार रूपए, मनेन्द्राढ़-चिरमिरी-भरतपुर के 60 मानस मंडली को 30 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है।

नंदनी रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट पावर हाउस, भिलाई के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:- 9303289950, 9827806026, 8962815243

प्रीति डैसेस

मेन्स एण्ड लेडिस वियर

जवाहर मार्केट, पावरहाउस, भिलाई
मो. 9589230033, 9993840094

- जीन्स
- टी-शर्ट
- शर्ट
- ट्राउजर

भारत जीन्स

जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई

BIHAR BOOT HOUSE

Jawahar Market, Power House
Bhilai 9826181183

आरना इंटरप्राइजेस

कांदावाला वाटरपरी फायरके विक्रेता एवं सुधारक

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं सीसीटीवी कैमरा के विक्रेता व सुधारक

सर्कुलर मार्केट केम्प-2, भिलाई, न्यू जेपी रोडदत्त के सामने

7828844440, 9993045122

नया बस स्टैण्ड, शिव मंदिर रोड, दुर्ग, 09981370285, 9302833333

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता

अनुप ट्रेडर्स

सर्कुलर मार्केट, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

प्रमोद इंटरप्राइजेस

गेंहू, चावल एवं दाल के थोक विक्रेता

लिंग रोड, केम्प-2, भिलाई-दुर्ग
फोन: 0788-2225449, 93290-13017

Hotel Shiv Prabha Inn. & Town King

The Family Restaurant

46-C Market, Near Sapana Talkies & Hotel Apana Keshari Lodge, Power House, Bhilai, Distt.-Burg (C.G.)

9893215251, 8966981590

Email:- ranjanaguptakeshary@gmail.com

BIHAR BOOT HOUSE

Jawahar Market, Power House
Bhilai 9826181183

खास खबर

कलेक्टर ने किया संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन

बालोद। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने प्रशासनिक दृष्टि से पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालयीन कार्य के सुचारु रूप से संचालन हेतु जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टरों एवं संयुक्त कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन किया है। इसके अंतर्गत संयुक्त कलेक्टर श्री योगेन्द्र श्रीवास को वरिष्ठ लिपिक शाखा 01, 02 एवं 03 तथा चिटपंङ शाखा के साथ-साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासकीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल को पर्यटन शाखा पर्यटन मण्डल से संबंधित कार्य तथा डिप्टी कलेक्टर मनोज मरकाम को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह नव पदस्थ डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा को वित्त एवं स्थापना, आहरण एवं संचितरण अधिकारी एवं प्रशासनिक कार्य, भू अभिलेख शाखा, लोक सेवा गारंटी, चिप्स/च्वाईस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एन.आई.सी.), लोक सेवा केन्द्र तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य प्रशासनिक कार्यों की निर्वहन की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा के लिंक ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर श्री सुरेश कुमार साहू को बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व में जारी किए गए शेष आदेश यथावत रहेगा।

गोरकापार गौठान के गोबर विक्रेता, कृषक एवं महिला समूह गोबर बेचकर हो रहे आत्मनिर्भर

बालोद। गोधन न्याय योजना अंतर्गत ग्राम गोरकापार गौठान से गोबर विक्रेता कृषक एवं महिला समूह गोबर बेचकर हो रहे आत्मनिर्भर। गोबर विक्रेता अर्जित लाभार्थि से संतुष्ट है। साथ ही ग्रामवासी भी संतुष्ट है। ग्राम गोरकापार के सामुदायिक पशु आश्रय स्थल का कुल रकबा 03 एकड़ है एवं चारागाह उद्यान का कुल रकबा 05 एकड़ है। जिसमें फ़त्तदार वृक्ष एवं मौसमी चारा लगाया जाता है। उक्त स्थल पर ग्राम सुखरी की समर्पित महिला स्वसहायता समूह के द्वारा गोबर खरीदी का कार्य किया जाता है। महिला समूह द्वारा अब तक 01 लाख 47 हजार 312 किलोग्राम गोबर खरीदी की गई जिसके एवज में 40 हजार 740 किलोग्राम वर्मी खाद उत्पादन कर विक्रय हेतु सेवा सहकारी समिती गोरकापार को दिया गया है, जिसका लाभार्थि महिला समूह को 78 हजार 578 रु. प्राप्त हो चुका है। अर्जित लाभार्थि का समूह की महिलाओं द्वारा अपने घरेलू आवश्यक सामग्री खरीदी कर आर्थिक जरूरत पूरी करने में मदद भी मिल रहा है। जिससे महिला समूह खुश होकर कार्य कर रही हैं। सामुदायिक पशु आश्रय स्थल ग्राम गोरकापार में कुल 27 पशुपालक है। जिनके द्वारा माह भर में प्रत्येक खरीदी दिवस पर अपने पशुधन द्वारा प्राप्त गोबर का विक्रय महिला समूह को किया जाता है। जिससे गोबर विक्रेता के 15 दिवस अंतराल में पशुपालकों के खाले में राशि अंतरित हो जाता है। साथ ही सामुदायिक पशु आश्रय स्थल में पशुओं के लिए चारा हेतु 175 क्विंटल पैरा उपलब्ध है। पशुओं के लिए पीने हेतु पर्याप्त मात्रा में जल एवं छाया उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मकाल में पशु खुले स्थानों में चराई करते हैं। वर्षाकाल में लावारिस पशुओं का एवं अन्य गौवंश पशुओं का अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न

सुकमा। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह ब्युम्बर्ग परियोजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टेक होल्डर्स का संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। ब्युम्बर्ग परियोजना के संभागीय सलाहकार एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. योगेश पैकरा ने उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छ.ग. संशोधन अधिनियम 2021, टोबैको मॉनिटरिंग एप्प से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में कलेक्टर हरिस, एस ने जिले में तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में की जा रही गतिविधियों की जानकारी नोडल अधिकारी से ली। साथ ही तम्बाकू नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने कहा। आगामी 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध अधिनियम दिवस में जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने कहा। साथ ही कोटपा 2003 के प्रावधानों की निगरानी तथा उल्लेघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला स्तरीय दल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुकमा को चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किये जाने के निर्देश दिए गए। सु प्रीति दुर्गम एसडीएम सुकमा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश सांडिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

सार्वजनिक-निजी सहयोगात्मक वित्त पोषण के प्रभाव को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली (पीआईबी)। अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के परिणामों को प्रदर्शित करने वाली एक दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में 22 मई, 2023 को किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादों और पेटेंट बनाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोगात्मक वित्त पोषण को सामने लाना था।

इम्प्रिंट परिणामों के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर सचिव, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता अपने सम्बोधन में कहा कि इम्प्रिंट पहल एक अनूठा उदाहरण है जहां सरकार और शिक्षा जगत शुरू से ही उद्योगों के साथ ऐसे विचारों पर काम कर रहे हैं जिन्हें बाजार में ले जाया जा सकता है, और इस योजना से कई प्रौद्योगिकियां और उत्पाद बाजार में पहुंच गए हैं। डॉ. गुप्ता ने कहा कि इस तरह के उद्योग-संचालित अनुसंधान के लिए समर्थन सार्वजनिक ङ्गनिजीङ्गसहभागिता (पीपीपी) मोड पर उद्योग द्वारा संचालित विचारों पर काम करने के मॉडल को स्वरूप देने



के साथ ही भारतीय उद्योग को और अधिक नवीन बना सकता है एवं अधिक गहन तकनीकी स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर सकता है तथा उन्हें विकसित देशों के बराबर उच्च स्तर पर बना सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड (डीएसटी /एसईआरबी) और शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की पहल की इस प्रदर्शनी जिसमें इम्प्रिंट ड्रइव के 10 कार्यक्षेत्रों (डोमेन) के अंतर्गत लगभग 60 परियोजनाओं के परिणाम को प्रोटोटाइप/पोस्टर/अन्य प्रासंगिक प्रदर्शनों के रूप में प्रदर्शित किया गया, लगभग लगभग विभिन्न हितधारकों से 300 व्यक्ति- वैज्ञानिक समुदाय, शिक्षाविद/शोधकर्ता, उद्योग, सरकारी अधिकारी आदि की भागीदारी देखी गई।

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने समाज में उन

समस्याओं की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया जहां प्रौद्योगिकी एक बदलवा ला सकती है और कहा कि इम्प्रिंट के अंतर्गत वे प्रौद्योगिकियां, जिनमें से कई प्रदर्शनी में प्रदर्शित हैं, का उद्देश्य समाज के लिए लाभकारी उत्पादों को सामने लाना है। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती सीम्या गुप्ता ने कहा कि अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी) - आईएमपीआरआईएनटी) जैसी पहलों ने समाज की जरूरतों को पूरा किया, उन्होंने प्रभाव पैदा करने के लिए सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी) - आईएमपीआरआईएनटी) योजना को 5 नवंबर, 2015 को 'मेक इन इंडिया'

पहल के अंतर्गत उच्च स्तर के नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो उद्योग की जरूरतों को सीधे प्रभावित करता है और इस तरह उद्योग के भारतीय विनिर्माण इकोसिस्टम की प्रतिस्पर्धात्मक बहुत में सुधार करता है। हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक 10 चयनित कार्यक्षेत्रों (डोमेन) में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य उन शोध परियोजनाओं के लिए सहयोगी वित्त पोषण करना था जो उत्पाद और पेटेंट तैयार करेंगे। ये 10 डोमेन हैं- पर्यावरण और जलवायु, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, टिकाऊ आवास, जल संसाधन, उन्नत सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी और सुरक्षा और रक्षा।

मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को नगर पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना



श्रीकंचनपथ न्यूज

कोण्डगांव। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 किरणमयी नायक के पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण तथा उनसे संबंधित राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का कोण्डगांव में स्थागत करते हुए जिले में प्रचार हेतु नगर पालिका परिषद अध्यक्ष वर्षा यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री महतारी रथ प्रदेश भर में कई जिलों में भ्रमण करते हुए कोण्डगांव पहुंची है। जिले में कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी एके बिस्वाल के निर्देशन में संचालित यह रथ 21 से 27 मई तक

विभिन्न ग्रामों में जाकर महिलाओं की सुरक्षा, उनके विकास एवं नारी सशक्तिकरण के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में घूम-घूम कर जन जन तक जानकारी प्रदान करेगा।

यह रथ बड़ीबेन्द्री, बड़ेकनेरा, चिपावन्ड, दहिकोंगा, नेवता, बफ्ना, किवाईबालेंगा, बयानार, बम्हनी, सोनाबाल, हसलनार, मर्दापाल, माकडी, छिनारी, शामपुर, अमरावती, बोरगांव, जुगापी, भण्डारशिवनी, लंजोड़ा, आलोर, बड़ोडंगर, कोटपाड़, बंगोली, धनोरा, अरंडी, बहीगांव, केशकाल, धामनपुरी, बड़बत्तर, मारंगपुरी, विश्रामपुरी में भ्रमण करेगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी रजनी दुवे, ठकेश्वर लोंडे, विभागीय पर्यवेक्षक तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्थानीय महिलाएं भी उपस्थित रहीं।

श्रद्धा सुमन मानस मंडली को जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता पुरस्कार दिया गया

श्रीकंचनपथ न्यूज

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता सारंगढ़ बस स्टैंड के पास सोमवार को आयोजित किया गया। राज्य सरकार के संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत सारंगढ़, सरिया, बरमकेला, बार, धारासिव, रेड़ा, बासीनबहरा, बरगाव आदि के मानस मंडली ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा आयोग के सदस्य पुरुषोत्तम साहू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम के दौरान विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उत्तरी जांगड़े सहित अतिथियों ने पंडाल में जिले के स्व सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण



किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि भगवान रामजी छत्तीसगढ़ के भांजा हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में भांजा भांजियों को प्रणाम करने की परंपरा है। प्रभु श्री राम हम सब के दिल में बसते हैं। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने संक्षिप्त उद्बोधन दिया। नोडल अधिकारी हरिशंकर

चौहान ने अपने संबोधन में गाकर कहा जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भरके देखा नहीं है। निर्णायक मंडल में श्रीमती व्ही ठाकुर, श्यामलाल चौहान, संतराम धृतलहरे और मानिक लाल मेहर शामिल थे। सभी प्रतिभागी मंडली और अन्य को मेडल से पुरस्कृत किया गया।

श्रीकंचनपथ न्यूज

मोहला। कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिले के सभी जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद सीईओ, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, गौठान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्वसहायता समूहों की बैठक लेकर गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन को विशेष प्राथमिकता देते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करें।

उन्होंने कहा कि गौठानों को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना बनाई गई है। जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि गौठान में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

कलेक्टर श्री जयवर्धन ने बताया कि 30 जून 2023 को



गौठान का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गौठानों में चल रहे कार्यों को गति देने एवं नये कार्यों को शुरू करने के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए सरपंच, सचिव, गौठान समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों और स्वसहायता समूह के सदस्यों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। गौठान में चल रहे निर्माण कार्यों एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्रतिदिन निश्चित प्रपत्र में जनपद सीईओ और एसडीएओ के संयुक्त हस्ताक्षर से शाम 4 बजे तक प्रेषित करने के

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट को मिला इंटरनेशनल अवार्ड

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। हांगकांग में 'द एसेट ग्रुप' द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित द एसेट ट्रिपल-ए अवार्ड्स समारोह में रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट को बेस्ट पेमेंट एंड कलेक्शन सॉल्यूशन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। एक भव्य समारोह में द एसेट ग्रुप के एडिटर एंड चीफ डेनियल वाय. यू. द्वारा रायपुर स्मार्ट सिटी लि. को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया।



रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के प्रबंध संचालक मयंक चतुर्वेदी ने प्रोजेक्ट से जुड़े नगर निगम, स्मार्ट सिटी व प्रोजेक्ट पार्टनर बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है एवं नागरिकों को इस सुविधा का पूर्ण लाभ के लिए प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के डीडीएन प्रोजेक्ट को डिजिटल अवार्ड अंतर्गत बेस्ट पेमेंट एंड कलेक्शन सॉल्यूशन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के तौर पर चयनित किया गया। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. व प्रोजेक्ट पार्टनर इंडसइंड बैंक द्वारा इस श्रेणी हेतु डीडीएन प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ज्युरी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विशेषज्ञ इन परियोजनाओं की गुणात्मक व जनोपयोगी स्वरूप का मूल्यांकन कर उपयोगिता अनुरूप अवार्ड का निर्धारण करते हैं। परियोजना के

तहत प्रोजेक्ट पार्टनर इंडसइंड बैंक के सहयोग से रायपुर स्मार्ट सिटी लि. व नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा शहर के 3.11 लाख घरों में डीडीएन प्लेट लगाए जा रहे है, जिसके माध्यम से मकान मालिक अपने इस प्लेट में लगे क्यू-आर कोड को स्कैन कर संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य विभिन्न करों के भुगतान के साथ ही डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, नल कनेक्शन सहित 26 तरह की आवश्यक व आपातकालीन सेवाएं घर बैठे सुगमता पूर्वक प्राप्त करते हैं। हाल ही में आयोजित एक भव्य समारोह में रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के डीडीएन प्रोजेक्ट को डिजिटल अवार्ड अंतर्गत बेस्ट पेमेंट एंड कलेक्शन सॉल्यूशन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के तौर पर चयनित किया गया। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. व प्रोजेक्ट पार्टनर इंडसइंड बैंक द्वारा इस श्रेणी हेतु डीडीएन प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया। रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा नगर निगम के सहयोग से अब तक 1.55 लाख घरों में डीडीएन प्लेट लगाए जा चुके है एवं 55 हजार घरों में उक्त प्लेट वर्तमान में लगाए जा रहे है।

गौठान में स्थानीय लोगों को जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति करें मजबूत - कलेक्टर

को गौठान के वर्मी टाका में पर्याप्त मात्रा में केचुआ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गौठानों में निरीक्षण पंजी संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वावलंबी गौठान के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जिन गौठानों में आगामी 3 पखवाड़े तक गोबर क्रय करने की राशि उपलब्ध हो ऐसे गौठानों को स्वावलंबी घोषित करने के लिए उप संचालक कृषि को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। जिन गौठानों में मल्टी एक्टिविटी का कार्य चल रहे है, उसकी जानकारी गोधन न्याय योजना के पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला नोडल अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री हेमंत ठाकुर, एसडीएम मोहला डॉ. हेमन्ध्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित योगी, जनपद सीईओ चौकी बीपी चुरेन्द्र, मोहला सीईओ गोपाल कंवर, मानपुर सीईओ डीडी मंडले, कार्य को 30 मई तक पूर्ण करने के लिए कहा। कलेक्टर जयवर्धन ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों

Shri Vijay Enterprises

Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

CAR DECOR

House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919 K. Satyanarayan

Ashok JEWELLERY

Gifts • Toys • Cosmetics
 Perfumes • Sia Jewellery

Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727

Mukesh Jain 9009959111
 Rishabh Jain 8103831329

Y Fitness

• Gym Servicing
 • Gym Equipment & Accessories Available
 • Home Treadmill & Gym Service Available

start 17500/-

Bajaj Finance Available

Shop No. 10, 14, Block, Street No.-7 Dakshi ga igolri, Supela, Bhilai Chhattisgarh

Facebook id - Protein Planet Bhilai
9098981555

SAIRAM Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

दास गार्मेन्ट्स

जॉस, शर्ट, टी-शर्ट, फ्राक सूट, फ्राक, फैसी सलवार सूट एवं क्टिस वियर,अंडर गार्मेन्ट्स, गाउन के लेटेस्ट कलेक्शन

एक बार अवश्य घूमाँ

गणेश मार्केट, गुरुद्वारा, रोड सुपेला, भिलाई, 7828248067

ख़ास - ख़बर

श्री गुरु संघ आश्रम द्वारा किया गया शरबत वितरण

भिलाई । सेक्टर 6 स्थित श्री गुरु संघ आश्रम द्वारा दिनांक 20 मई को शरबत वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष शरबत वितरण सहित विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के कार्य किये जाते हैं। श्री गुरु संघ के संस्थापक आचार्य दुर्गा प्रसन्न परमहंस देव जी के पुण्य स्मृति में समाज सेवामूलक कार्य किये जाते हैं। इस अवसर पर संस्था के सभी सदस्यगण उपस्थित थे।

किराएदारी में निवासरत तथा व्यवस्थापन वाले हितग्राहियों को आवास प्रदान करने के लिए निकाली जाएगी लॉटरी

भिलाई । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान, मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत केनाल रोड एवं अन्य विकास कार्यों से प्रभावित हितग्राही जिन्हें बेखुशली व्यवस्थापन हेतु सूचना पत्र जारी किया जा चुका है। इनमें से पात्र हितग्राहियों को जिन्होंने अंशदान की राशि जमा कर दी है आवास आवंटित किया जाना है। कुल पात्र हितग्राही 689 में से 218 हितग्राहियों द्वारा मोर जमीन मोर आस के तहत राशि जमा कर दी गई है तथा मोर जमीन मोर चिन्हारी के 17 हितग्राही है। जिन पात्र हितग्राहियों ने अंशदान की राशि जमा की है उन्हें लॉटरी में शामिल किया जाएगा। दिनांक 24 मई 2023 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे आवास आवंटन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। आवास प्रभारी विद्याधर ने बताया लॉटरी का स्थल नगर पालिक निगम भिलाई मुख्य कार्यालय सुपेला में रहेगा। लॉटरी में शामिल होने के लिए हितग्राही अपना अंशदान जमा राशि रसीद की मूल प्रति, मूल आधार कार्ड, आवेदन पत्र की पावती तथा लॉटरी में शामिल होने हेतु जारी सूचना पत्र के साथ निर्धारित स्थल एवं समय में स्वयं उपस्थित रहेंगे। दिव्यंग एवं वरिष्ठ जनों को उनके दस्तावेज परीक्षण के आधार पर भूतल का आवास आवंटन किया जाएगा।

बीएसपी सीएसआर द्वारा पतोरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन

भिलाई । सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग द्वारा आदर्श इस्पात ग्राम पतोरा में दिनांक 23 मई, 2023 को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुए शिविर में सामान्य जांच, शुगर, बीपी के अतिरिक्त निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। इस शिविर में कुल 26 लोगों की जांच करके उनको दवाई वितरण किया गया, जिसमें 16 पुरुष, 09 महिलाएं तथा 01 बच्चा शामिल था। ग्राम पंचायत भवन में ही शिविर का आयोजन किया गया। आदर्श इस्पात ग्राम पतोरा में आयोजित चिकित्सा शिविर में ग्राम सरपंच श्रीमती अंजिता गोपेश एवं सीएसआर मेडिकल टीम की ओर से डॉ ईशा कुजूर, बीपी व शुगर परीक्षण हेतु श्रीमती रेखा देव, फर्मासिस्ट खिलावन कुंभकार, पंजीकरण हेतु शंभू और विभागीय प्रतिनिधि व सीएसआर सहायक ए के सोनी उपस्थित थे। इस शिविर में सामान्य जांच के साथ मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने आस-पास के परिधीय क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा का काम लंबे समय से उपलब्ध कराता आ रहा है। इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के सीएसआर विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है। बीएसपी द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का उद्देश्य गांव के अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा का लाभ पहुंचाना है।

अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए शीघ्र करे आवेदन नियमितीकरण आवेदन करने के लिए आसान है प्रक्रिया देखें पूरी जानकारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई । नियमों के विपरीत निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण करने का सुनहरा अवसर उन्हें मिल रहा है, इसलिए आवेदन करने में विलंब न करें शीघ्र ही नियमितीकरण के लिए आवेदन कर नियमितीकरण करा लें, क्योंकि निर्धारित तिथि के अनुसार नियमितीकरण कराने के लिए कुछ ही समय शेष है। निगम में आवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों का नियमितीकरण हो चुका है।

भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलाकर जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा कर दिया है, उनमें से अधिकतर लोगों के नियमितीकरण हो चुके हैं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया को भिलाई निगम द्वारा शीघ्रता से अपनाया जा रहा है। इन अनाधिकृत विकास

विधायक देवेंद्र यादव ने किया वार्ड 49 सुभाष नगर खुर्सीपार में भेंट मुलाकात

जमीन पर बैठकर विधायक ने किया भोजन, आम नागरिक के घर में चरवा रोटी और चौलाई भाजी का स्वाद

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई । नगर निगम भिलाई जोन 4 क्षेत्र के वार्ड 49 सुभाष नगर न्यू खुर्सीपार में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड का दौरा किया और लोगों से भेंट मुलाकात की। भेंट मुलाकात के दौरान कल रात हो गया था,वे वार्ड में ही लोगों से मिल रहे थे। तभी एक परिवार ने विधायक श्री यादव से अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन के लिए आग्रह किया।

वे इतने प्रेम, आदर भाव और सम्मान भोजन के लिए कहा कि विधायक उन्हें मना नहीं कर पाए। एक सामान्य आम नागरिक के आग्रह पर उ के परिवार के साथ जमीन पर बैठकर विधायक श्री यादव ने बड़े ही और हर्ष से भोजन किया। घर मे रोटी और चौलाई भाजी की सब्जी बनी थी। विधायक श्री यादव ने भी चौलाई भाजी



और रोटा का स्वाद चखा। विधायक श्री यादव ने पूरे परिवार का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा इतना अपना पन, इतना प्रेम उन्होंने जो दिया है। माता के हाथ की रोटी और सब्जी में इतना प्यार और आशीर्वाद है। इस भोजन को ग्रहण कर वे धन्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस प्रेम और सम्मान का वे कभी कर्ज चुका नहीं पाएंगे। परिवजनों ने विधायक से कहा कि आप का सौम्य,सुंदर, निर्मल व्यक्तित्व हम

सब का दिल जीत लिया। जमीन पर बैठकर कर बड़े प्यास से भोजन किये। एक आम नागरिक की तरह उनका व्यवहार, विधायक होते हुए भी को घमंड नहीं,सब से विनम्रता से पेश आना, सब की मदद करना। बड़ी बात है। भेंट मुलाकात के दौरान लोगों से मिले उनका हालचाल जाना वरिष्ठ नागरिकों से आशीर्वाद लिए। वार्ड युवाओं को गले लगाया।

वार्ड भ्रमण के दौरान वे माँ काली

के मंदिर पहुंचे। दर्शन किए सभी की खुशहाली को कामना की। इस दौरान वार्ड में बैठक भी आयोजित की गई। जिसमें वार्ड के युवा महिला व वरिष्ठ नागरिक जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक यादव वाक्य स्कूली छात्र छात्राओं से भी मिले उनसे पढ़ाई के बारे में चर्चा की और स्कूलों में सुविधाओं की जानकारी ली सभी आत्मा निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने विधायक देवेंद्र यादव को बताया कि उनके स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है पूरे स्कूल में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाया जाता है शहर मैडम भी बहुत अच्छे हैं स्कूल में भी काफी सुविधाएं और डेवलपमेंट किए गए हैं।

सभी से विधायक शहर और वार्ड के विकास पर चर्चा की। । वार्ड के कुछ नागरिकों ने बैठक में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं व मांग भी रखी। तब विधायक देवेंद्र यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समस्याओं का तत्काल निराकरण करे।

नगर के विकास और निर्माण के लिए चल रहे कार्य पर कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आज ली गई अर्बन की बैठक में नगर के विकास और निर्माण के लिए किए जा रहे योजनाबद्ध चरण पर चर्चा की गई। जिसमें चारों नगरीय निकाय के डेवलपमेंट के संबंध में उपस्थित संबंधित अधिकारी से कलेक्टर द्वारा जानकारी मांगी गई। बैठक में नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में आयुक्त श्री अजय त्रिपाठी द्वारा नगरी निकाय के विकास के लिए किये जा रहे रोड मैप का प्रस्तुत किया गया।

जिसके अंतर्गत आदर्श व्यवसायिक परिसर हेतु चिन्हित मार्केट निहारिका (सिरसा चौक के पास) , भिलाई 03 मार्केट (वार्ड क्रमांक 16 पुरानी भिलाई बाजार चौक के पास) व (चरोदा मार्केटलाइन जीई रोड के किनारे) में चल रहे डेवलपमेंट के संबंध में आयुक्त द्वारा जानकारी मुहैया कराई गई। आयुक्त ने कलेक्टर को बताया कि उक्त चिन्हित सभी क्षेत्रों में यातायात का अत्याधिक भार है। इसलिए इन क्षेत्रों के निकटतम स्थल पर पार्किंग के लिए स्थान

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमण्डल ने निगम आयुक्त से भेंटकर नियमितिकरण के संबंध में की चर्चा

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई । छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, भिलाई इकाई के प्रतिनिधिमण्डल ने निगम आयुक्त से भेंटकर उनसे नियमितिकरण के संबंध में चर्चा की। चेम्बर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन व भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधिमण्डल ने सभी व्यापारियों द्वारा नियमितिकरण के लिए जमा किये गये दस्तावेजों की पावती निगम आयुक्त को सौंपकर उनसे इस महत्वपूर्ण कार्य को जल्द पूर्ण कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यापारी साथी निगम की इस पहल की सराहना करता है और नियमितिकरण की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार है। चेम्बर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई निगम द्वारा सभी बाजारों में नियमितिकरण के लिए शिविर लगाये गये थे जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी साथियों ने लाभ उठाते हुए अपने-अपने दस्तावेज



जमा किये हैं। इस संबंध में चेम्बर प्रतिनिधिमण्डल ने निगम आयुक्त से भेंटकर उन्हें जोन -3 के अंतर्गत पावर हाउस के व्यापारियों की पावती सौंपी है और इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यापारी साथी नियमितिकरण के तय राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, इसलिए शीघ्रता शीघ्र इस कार्य को पूरा किया जाये। इस कार्य के जल्द पूे होने से बचे हुए व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वे भी नियमितिकरण कराने के लिए

आगे आयेंगे।

भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र ने बताया कि नियमितिकरण की प्रक्रिया के तहत व्यापारियों द्वारा अपने सारे दस्तावेज निगम द्वारा आयोजित शिविर के माध्यम से जमा किये जा चुके हैं। अब इस संबंध में हमने निगम आयुक्त से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है जिसमें निगम द्वारा स्थल का अवलोकन कर इसे टाउन एण्ड कंट्री विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा, जिसके पश्चात राशि भुगतान के

आवेदन करना होगा। आवेदन निर्धारित

प्राप्‍रूप में चेक लिस्‍ट के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड किया जा सकता है। आर्किटेक्‍ट की सूची भी इस वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अनाधिकृत निर्माण दिनांक 14 जुलाई 2022 के पूर्व से निर्मित है इस संबंध में साक्ष्य के रूप में भवन का बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जिसमें तारीख अंकित हो जमा करना आवश्‍यक है, अन्य दस्तावेज आवेदन के प्राप्‍रूप एक में चेक लिस्‍ट के अनुसार संलग्न करके आवेदन करना होगा।

नियमितीकरण कराने के लिए अधिक जानकारी के संबंध में इस नंबर पर करें

संपर्क नियमितीकरण करवाने के लिए भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 93999414300 पर संपर्क कर सकते हैं तथा नियमितीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत शहर के प्रमुख मार्केट क्षेत्र जवाहर मार्केट, सर्कुलर मार्केट तथा पावर हाउस सब्जी मंडी क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के बहिष्कार को लेकर जन जागरूकता रैली भिलाई निगम के कर्मचारियों तथा आम नागरिकों के द्वारा निकाली गई। इस दौरान बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। मार्केट क्षेत्रों एवं आम नागरिकों से अपील किया गया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करें। घरों से सब्जी एवं अन्य सामग्री लेने निकलने पर हमेशा अपने साथ कपड़े से बना थैला आदि लेकर निकले। बावजूद इसके यदि विक्रेताओं के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय किया जाता है तो उनके ऊपर जुर्माना की कार्यवाही निगम के द्वारा की जाएगी। कार्यवाही के चलते अब मार्केट



क्षेत्रों में प्रतिबंधित प्लास्टिक नजर नहीं आने लगा है। लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और वह प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने भी आम नागरिकों से प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल उस प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एक बार करने के बाद इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, झिल्ली, पन्नी आदि सार्वजनिक स्थानों में बिखरकर गंदगी फैलाते हैं, पशु भी अनजाने में इसका सेवन कर

नेहरू आर्ट गैलरी में श्रीमती इंदु चटर्जी द्वारा निर्मित पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन कल

श्रीकंचनपथ न्यूज

स्थानीय विमानतल में 4 से 5 बार की गई। श्रीमती चटर्जी ने बताया कि कलाप्रेमियों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं उन्हें बेहद प्रोत्साहित करती है।

गौरतलब है कि विश्व की सबसे बड़ी रंगोली में श्रीमती इंदु चटर्जी का नाम लिम्का बुक में भी दर्ज है। इन्होंने सेंट्रल जेल के महिला प्रकोष्ठ में महिलाओं की काउंसिलिंग करने के साथ विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण भी दिया। स्थानीय रायपुर रेलवे स्टेशन के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए काम किया। श्रीमती चटर्जी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग रायपुर के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल श्री शेखर दत्त (2010) एवं माननीय मुख्य मंत्री रमन सिंह (2010) द्वारा सम्मानित हो चुकीं हैं। यह तीन दिवसीय इस चित्रकला प्रदर्शनी 25 से 27 मई 2023 तक प्रतिदिन संध्या 5.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक आम जनता के दर्शनार्थ खुली रहेगी।

शहर में पेयजल संकट के लिए नगर निगम की पिछली परिषद जिम्मेदार

भूपेश सरकार ने साढ़े 4 साल में दुर्ग शहर में कराए ऐतिहासिक विकास कार्य : वोरा

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने दुर्ग में जलसंकट के विरोध में 24 मई को भाजपा के नगर निगम के घेराव प्रदर्शन को बेसिर-पैर का प्रदर्शन बताया है। वोरा ने कहा कि दुर्ग में पेयजल संकट को लेकर तमाम अव्यवस्थाओं के लिए खुद भाजपा ही जिम्मेदार है।

20 साल तक नगर निगम की सत्ता में भाजपा काबिज रही और राज्य में 15 साल तक भाजपा का शासनकाल रहा। इसके बावजूद शहर की पानी सप्लाई व्यवस्था नहीं सुधरी। चुनाव सामने देखकर मुदाविहीन भाजपा बौखला गई है

और इसी बौखलाहट में दुर्ग नगर निगम में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।

वोरा ने कहा कि बीते साढ़े चार साल के कांग्रेस शासनकाल में राज्य सरकार ने दुर्ग के विकास के लिए चार सौ करोड़ से अधिक राशि जारी की है। इस राशि से पेयजल संकट सहित नगर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। शहर के चौमुखी विकास को देखकर भाजपा नेताओं की नौद उड़ गई है। 64 करोड़ की लागत से जीई रोड के उन्नयन सहित गौरवपथ निर्माण, शिवनाथ रिवर प्र्रंथ योजना, उगड़ा बांध पिकनिक स्पोर्ट योजना, शहर में करोड़ों रुपए की लागत से जगमग रौशनी बिखेरने सहित शहर का चौमुखी विकास किया जा रहा है। वोरा ने

कहा कि पेयजल संकट के स्थायी निवारण के लिए वे स्वयं लगातार प्रयासरत है। कुछ वार्डों में पेयजल समस्या की जानकारी मिलने पर उन्होंने निगम कमिश्नर को तत्काल समस्या का समाधान करने कहा।

निगम की टीम मौके पर जाकर व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। वोरा ने कहा कि भाजपा नेता चार साल तक कुंभकर्णी नौद में सोते रहे हैं। उन्होंने जनता की सुध नहीं ली है। आगामी विधानसभा चुनाव में केवल चुनावी लाभ के लिए भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन, भाजपा का असली चेहरा आम जनता अच्छी तरह देख चुकी है। आम जनता भाजपा के झंसे में नहीं आएगी।